06 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सुशासन का माडल दिया।

24 लाख से अधिक किसानों को किसान मानधन योजना के तहत कार्ड उपलब्ध कराए गए।

कानून का राज देखा तो दौड़े चले आए निवेशक

10 11 व 12 फरवरी को राजधानी लखनऊ में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में अपनी पूरी टीम के साथ जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि इस आयोजन से प्रदेश में आर्थिक क्रांति की शुरुआत होगी और सरकार ने इसके लिए पूरे मनोयोग से धरातल तैयार कर लिया है। वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की दृष्टि बदली है और इसे हम सभी ने देश-विदेश में हुए रोड शो के दौरान महसूस किया और इसी कारण से हमारे साथ उम्मीद से अधिक निवेशक जुड़ने के लिए तैयार हैं। विपक्षी दलों की आलोचनाओं की परवाह किए बगैर योगी कहते हैं कि सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 के पहले प्रदेश का क्या हाल था। आज कानून का राज है और अपराधियों के हौसले पस्त हैं। हम भाई-भतीजावाद में नहीं, समग्र विकास में विश्वास रखते हैं और इसीलिए बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों तक उद्योगपति पहुंच रहे हैं। अपने सरकारी आवास पर दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश संपादक आशुतोष शुक्ल और उप्र ब्यूरो प्रमुख अजय जायसवाल से मुख्यमंत्री ने विस्तृत बातचीत की-

• कभी बीमारू राज्य कहलाने वाले यूपी में अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस) और जी20 सम्मेलन होने जा रहे हैं। अपने छह वर्ष के कार्यकाल में यूपी की छवि में आए बदलाव को आप कैसे देखते हैं?

डबल इंजन की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुशासन का माडल दिया है। पहले की सरकारें भाई-भतीजावाद, परिवारवाद और जातिवाद के चलते प्रदेश के विकास के बारे में सोचती भी नहीं थी। वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने कानून व्यवस्था सुधारने के साथ ही सुनियोजित तरीके से प्रदेश के विकास के बारे में बड़े पैमाने पर काम किया। बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से प्रदेश की जनता को सुरक्षित परिवेश प्रदान कर सांप्रदायिक एवं जातिगत सौहार्द कायम रखा गया। प्रदेश दंगा मुक्त रहा जबकि बसपा सरकार में 364 दंगे और पूर्व की अखिलेश सरकार में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे।

• जीआइएस के जरिए 17 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश को सुनिश्चित करने के पीछे आपकी क्या रणनीति रही?

10 फरवरी से तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने से पहले हमने 25 अलग-अलग सेक्टर की नीतियों को नए सिरे से बनाया है। हमारी सभी नीतियां दूसरों से बेहतर और व्यावहारिक हैं। हमारी टीम ने दुनिया के 16 देश और आठ शहरों में रोड शो आदि किए। यही कारण है कि सभी सेक्टर में 17 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश में बड़ी-बड़ी कंपनियां निवेश करना चाहती है। वैसे तो वर्ष 2020-21 में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने की तैयारी थी लेकिन कोरोना के प्रभाव के चलते तब नहीं किया जा सका। अब पूरी तैयारी के साथ समिट करने के बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

मेरा दफ्तर मानीटरिंग करेगा निवेशकों को शिकायतें न हों

• ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आप बहुत सजग सक्रिय दिखते हैं, लेकिन उसके प्रति वही सजगता कुछ अन्य मंत्रियों में नहीं दिखती। ऐसे में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना आपके लिए चुनौती नहीं होगी?

देखिए, काम टीम करती है और कर भी रही है। यह जो आपको काम दिख रहा है, यह टीम वर्क का ही परिणाम है। हमने निवेश मित्र बनाया है जो समिट की पहले और बाद की प्रगति पर पूरी दृष्टि रखेंगे। हर चीज को हमने तकनीक आधारित बना दिया है। वहीं कोई सुझाव या फिर शिकायत आती है तो उसका उत्तर देना ही होगा। हर उत्तर की समय सीमा बना दी गई है और इसके भीतर ही निवेशक को उसके प्रश्नों या समस्या का समाधान देना होगा। सभी लोग इसमें मन से जुटे भी हैं और काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय एक-एक चीज की मानीटरिंग कर रहा है और आगे भी लगातार करता रहेगा। यह समिट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रही है तो हम भी कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। ढिलाई नहीं होने दी जाएगी।

• वर्ष 2017 में सत्ता संभालने के एक वर्ष के अंदर फरवरी 2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में करीब एक हजार कंपनियों से 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश के करार हुए थे। इनमें से अब तक कितने जमीन पर उतरे। निवेश और रोजगार सृजन की दृष्टि से पिछली इन्वेस्टर्स समिट कितनी लाभकारी रही?

प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार से देश-दुनिया में यूपी के प्रति धारणा बदली तो निवेश की नई राह खुली। सरकार बनाने के एक वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही फरवरी 2018 में समिट आयोजित करने के बाद हमने तीन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। इनमें से दो सेरेमनी तो कोरोना काल के पहले हुई थी। मैं कह सकता हूं कि लगभग चार लाख करोड़ रुपये के 80 प्रतिशत से ज्यादा एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। इससे दो करोड़ युवाओं को रोजगार मिला।

• यूपी की कानून व्यवस्था सदैव बड़ा मुद्दा रही है। क्या मानते हैं कि पूर्व में खराब कानून व्यवस्था के चलते ही उद्योगपति यूपी में निवेश को आगे नहीं आते थे। उद्योगों व उनके कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था प्रस्तावित है?

हमने अपने संकल्प पत्र में अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की बात कही थी जिसे हमने पूरा भी किया है। चूंकि विकास की बुनियादी शर्त सुरक्षा और कानून का राज है इसलिए हमने दोनों के ही उच्च मापदंड प्रस्तुत किए हैं। प्रत्येक नागरिक से लेकर हर एक निवेशक और उसके निवेश की हर प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। इससे यूपी के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। निवेशकों का शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। हमने राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने के लिए अलग से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल) नाम से नए सुरक्षा बल का गठन किया है। ईप्रासीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में भी आज उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।

• निवेशकों को सुविधाएं देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सबसे पहले उद्योगों की सुगमता के लिए 241 रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन कम किए गए हैं। ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेशकों के लिए डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल द्वारा निवेश मित्र योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से 362 से अधिक आनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आज स्थिति यह है कि ईज आफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश अचीवर्स राज्य बन गया है। हमने कोरोना के दौरान भी उद्योगों को बंद नहीं होने दिया।

• सपा सहित विपक्षी दल इन्वेस्टर्स समिट पर सवाल उठाते हुए इसे धोखा और कुछ खास बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला आयोजन बता रहे हैं। वह कहते हैं कि एमओयू पर हस्ताक्षर का मतलब निवेश आना नहीं है?

आप जानते हैं कि वर्ष 2017 से पहले यूपी की कानून व्यवस्था का क्या हाल था? कोई भी यूपी में निवेश करने के लिए आना ही नहीं चाहता था। निवेश के नाम पर जिसे इन्वेस्टर्स समिट कहा जाता था वह दरअसल रोड शो से ज्यादा कुछ नहीं होता था। हमने न केवल उद्यमियों के साथ एमओयू किए बल्कि उन्हें धरातल पर उतारना भी सुनिश्चित किया है। हम जो कर रहे हैं उसे जनता देख रही है।

• आपने पुलिस रिफार्म के तहत अहम निर्णय किए हैं। पुलिस भर्ती, आधुनिकीकरण, अवस्थापना सुविधाओं के साथ ही कमिश्नरेट प्रणाली लागू की है?

कानून व्यवस्था पर नियंत्रण हमारी शुरू से ही प्राथमिकता रही है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। हमने सुनिश्चित किया है कि पुलिस विभाग के पास संसाधनों की कमी न होने पाए। हमने बिना भेदभाव के पुलिस भर्ती की। पहले की सरकारों में किस तरह के मामले सामने आते थे, यह सबने देखा ही है।

• महिलाओं को सुरक्षा के साथ स्वावलंबी बनाने की दिशा में आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

हमारी सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान चला रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तीन महिला बटालियन आदि का गठन किया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट से साफ है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने में 59.1 प्रतिशत की दर से प्रदेश फिर देश में पहले पायदान पर है।

10 फरवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले 25 अलग-अलग सेक्टर की नीतियों को नए सिरे से बनाया गया।

2.60 करोड़ किसानों के बीच लागत कम करने के उद्देश्य से 51,640 करोड़ की राशि हस्तांतरित।

16 देश और आठ शहरों में प्रदेश सरकार की टीमों ने रोड शो आदि किए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला।

04 लाख करोड़ के 80% से ज्यादा एमओयू धरातल पर हैं, 83 हजार ओडीओपी कारीगरों को बांटे टूलकिट।

10 लाख युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा था और इनमें से 40 प्रतिशत से अधिक को रोजगार मिल चुका है।

19 मार्च 2017 से लेकर अब तक गन्ना किसानों को 1.90 लाख करोड़ के रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया।

173 दुर्दांत अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, 50 माफिया व गैंग पर सख्त कार्रवाई।

17 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव सभी सेक्टर में अब तक